शिक्षा में नवाचार और उनका मूल्यांकन

डॉ. अमन मदान

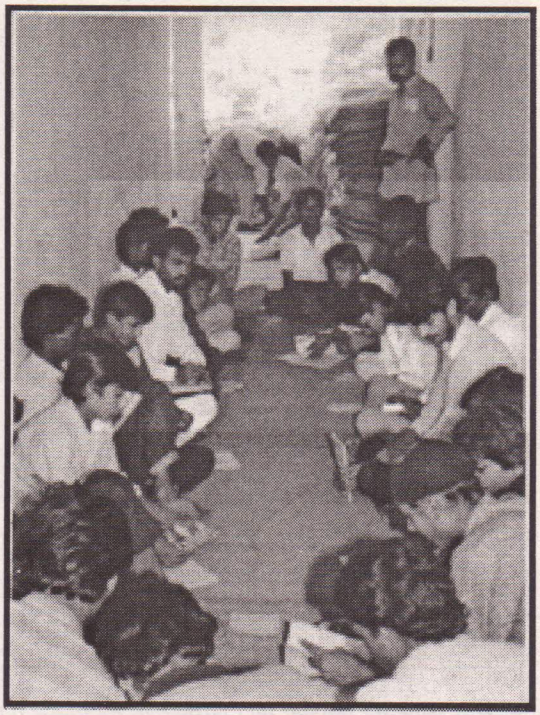

नवाचारों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक सतत् प्रक्रिया ज़रूरी है। इस प्रक्रिया के ज़रिए ही अच्छे विचारों को चुना जा सकता है और कम अच्छे विचारों से सबक सीखे जा सकते हैं। इसी प्रक्रिया के माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था लगातार बेहतर बनेगी। किन्तु भारत में हम आज भी शैक्षिक मूल्यांकन की उपयुक्त विधियां विकसित करने में जूझ रहे हैं।

पिछले वर्षों में मध्यप्रदेश तीन प्रमुख शैक्षिक नवाचारों का गवाह रहा है। ये नवाचार हैं - राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन द्वारा लागू की गई शिक्षा गारंटी योजना, गैर सरकारी संगठन एकलव्य द्वारा बैतूल के शाहपुर ब्लॉक में चलाया जा रहा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (प्राशिका) और मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा कई गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से लागू किया गया सीखना-सिखाना पैकेज।

मध्यप्रदेश शैक्षिक नवाचारों की दृष्टि से अग्रणी रहा है; यहां सीखने सिखाने के विविध दर्शनों व रणनीतियों के परीक्षण की गुंजाइश विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाती रही है। देखा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में परखे गए विचारों को आज देश के कई हिस्सों में शिक्षा की मुख्यधारा में अपनाया जा रहा है। भारत के अन्य प्रदेशों में शिक्षा का जो मोनोकल्चर है उसकी अपेक्षा विविध फूलों को खिलने का मौका देना कहीं अधिक लाभप्रद रहा है।

मूल्यांकन का सवाल

नवाचारों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक सतत् प्रक्रिया ज़रूरी है। इस प्रक्रिया के ज़रिए ही अच्छे विचारों को चुना जा सकता है और सबक सीखे जा सकते हैं। इसी प्रक्रिया के माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था लगातार बेहतर बनेगी। किन्तु आज भी शैक्षिक नवाचारों के मूल्यांकन में तथा उनके सबक को नीतिगत नियोजन में शामिल करने के मामले में कई खामियां नज़र आती हैं। कई अन्य देशों के विपरीत हम आज भी शैक्षिक मूल्यांकन की उपयुक्त विधियां विकसित करने में जूझ रहे हैं।

भारत में समय-समय पर विभिन्न शैक्षणिक पैकेजों के मूल्यांकन हुए हैं किन्तु इन सभी में स्वयं मूल्यांकन करने वालों ने माना है कि उनका काम एक उपयुक्त विधि की तलाश की प्रक्रिया का एक हिस्सा ही है। यदि हम अतीत के अनुभवों का उपयोग बेहतर भविष्य के लिए करना चाहते हैं, तो उपयुक्त मूल्यांकन विधियां विकसित करना अनिवार्य है।

तीन नवाचारों का मूल्यांकन

मूल्यांकन के बारे में एक महत्वपूर्ण कदम अहमदाबाद

के भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) के रवि जे. मथाई सेंटर फॉर एजुकेशनल इनोवेशन ने उठाया है। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन ने नवाचार के उपरोक्त तीनों पैकेजों - शिक्षा गारंटी योजना, प्राशिका और सीखना-सिखाना पैकेज के मूल्यांकन का काम इस सेंटर को सौंपा। सेंटर ने इनके मूल्यांकन हेतु गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों तरह की तकनीकों का मिला-जुला उपयोग किया। उनके अध्ययन की प्रमुख तकनीक गुणात्मक है जिसके अंतर्गत केस स्टडीज़ की गईं, शिक्षकों से साक्षात्कार किए गए और पाठ्यपुस्तकों की मेज़ी समीक्षा की गई।

वास्तव में जटिल समस्याओं को सम्भालने के लिए गुणात्मक तकनीक ही बेहतर रहती है। उक्त तीन पैकेजों के मूल्यांकन की समस्या काफी पेचीदा है क्योंकि शिक्षा की किसी भी रणनीति के परिणाम पर तमाम बातों का असर पड़ सकता है। सेंटर ने अपने अध्ययन के दौरान कई परीक्षणों के ज़रिए बच्चों के प्रदर्शन का मात्रात्मक मूल्यांकन भी किया। मगर सेंटर की टीम इन मात्रात्मक आंकड़ों से बहुत अधिक निष्कर्ष निकालने को तैयार नहीं है क्योंकि उनका सर्वेक्षण पूरा नहीं हो पाया था और उन्हें अधूरे आंकड़ों से ही काम चलाना पड़ा था। विभिन्न पैकेजों के संगठनात्मक पहलुओं को अध्ययन में शामिल नहीं किया गया था। यह अध्ययन मूलतः इन तीनों पैकेजों के शैक्षिक व शिक्षा पद्धति सम्बंधी पहलुओं की छानबीन करता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान की टीम ने इस बात को ज़ोर देकर कहा है कि उन्होंने इन अलग-अलग पैकेजों की परस्पर तुलना का प्रयास नहीं किया है। उनका यह भी कहना है कि उनके पास ऐसा कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है, जिससे वे इतने अलग-अलग दर्शनों पर आधारित व इतने अलग-अलग संगठनात्मक ढांचों से संचालित पैकेजों की तुलना कर सकें। अलबत्ता, अपने सीमित लक्ष्य के बावजूद वे ऐसी कई शैक्षिक रणनीतियों को पहचान पाए हैं जो कारगर रही हैं और जिनको आगे परीक्षण करके ज़्यादा बड़े पैमाने पर लागू करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

शिक्षक प्रशिक्षण

अध्ययन की रिर्पोट से पता चलता है कि एकलव्य और शिक्षा गारंटी योजना के पैकेजों में शिक्षकों के प्रशिक्षण व उत्साहवर्धन के लिए किए गए प्रयास काफी लाभदायक रहे हैं। एकलव्य के प्राथमिक शिक्षण कार्यक्रम से सम्बद्ध सभी शिक्षक सरकारी स्कूलों के नियमित शिक्षक हैं। इन शिक्षकों ने शिक्षण को आनन्ददायी व रोचक बनाने के महत्व को आत्मसात कर लिया है। उनमें समस्या सुलझाने के प्रति एक उत्साह और विश्लेषणात्मक सोच परिलक्षित होता है। वे अपने शिक्षण को स्थानीय पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास भी करते है। दूसरी ओर, शिक्षा गारंटी योजना के शिक्षकों की नियुक्ति अल्पकालिक है लेकिन उनको सबसे अधिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। उन्हें अपने पैकेज पर काफी विश्वास है। वे भी रोचक ढंग से, खेल-खेल में सिखाने का महत्व समझते हैं। प्राशिका (एकलव्य) और शिक्षा गारंटी योजना, दोनों से सम्बद्ध शिक्षकों ने स्कूल के मामलों में समुदाय को शामिल करने के महत्व पर ज़ोर दिया। यह बात गौरतलब है कि मात्र अच्छे प्रशिक्षण से शिक्षकों के प्रदर्शन में सुधार आया लगता है। यह तथ्य आजकल प्रचलित इस नीति पर

टीम ने इस बात को ज़ोर देकर कहा है कि उन्होंने इन अलग-अलग पैकेजों की परस्पर तुलना का प्रयास नहीं किया है। उनका यह भी कहना है कि उनके पास ऐसा कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है, जिससे वे इतने अलग-अलग दर्शनों पर आधारित व इतने अलग-अलग संगठनात्मक ढांचों से संचालित पैकेजों की तुलना कर सकें।

सवालिया निशान लगाता है कि स्कूली शिक्षकों से अच्छा काम करवाने का तरीका यही है कि उन्हें अल्पकालिक नियुक्ति दी जाए और असुरक्षा की तलवार उनके सिर पर लटकती रहे।

पाठ्यपुस्तकें

तीनों पैकेजों में पाठ्यपुस्तकें विकसित करने में काफी मेहनत की गई है। तीनों पैकेजों की पाठ्यपुस्तकों की एक विशेषता यह है कि तीनों में ही गतिविधियां जोड़ने के प्रयास हुए हैं और तीनों में ही बच्चों को मौका दिया गया है कि वे प्रारंभिक अवस्था से ही शब्दों, वाक्यों और अंकों के साथ सीधे सम्पर्क में आएं। बच्चों को इन अनुभवों के आधार पर वर्णमाला और संख्याएं सिखाने की कोशिश की गई है।

शिक्षा गारंटी योजना और सीखना-सिखाना पैकेज की पाठ्यपुस्तकें ज़्यादा व्यवस्थित ढांचे में बंधी हैं। यदि पैकेज का क्रियान्वयन अल्प प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाना है, तो इसे एक गुण माना जा सकता है। एकलव्य की पाठ्यपुस्तकों में बुनियादी क्षमताओं का अध्यापन अपेक्षाकृत कम ढांचाबद्ध ढंग से होता है। इसे लागू करने के लिए शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण की ज़रूरत है तथा शिक्षकों से ज़्यादा मेहनत की भी मांग होगी। अलबत्ता यदि मात्र बुनियादी क्षमताओं से आगे जाकर देखें तो एकलव्य की पाठ्यपुस्तकें बच्चों में सृजनात्मक, आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देने के मामले में अव्वल हैं। वे सचमुच बच्चों को खेल-खेल में सीखने का न्योता देती हैं।

कक्षा का माहौल

शिक्षा गारंटी योजना के पैकेज ने कक्षा में अध्यापन कार्य की शैली में बुनियादी परिवर्तन किए हैं। इस योजना के तहत राजस्थान के गैर सरकारी संगठन दिगन्तर द्वारा लागू की गई गैर-कक्षा-विभाजन पद्धति अपनाई गई है। अर्थात बच्चों को पहली, दूसरी वगैरह कक्षा में नहीं बांटा जाता। जब कोई विषय पढ़ाया जाता है तो बच्चे उस विषय में अपनी-अपनी दक्षता के अनुरूप समूह में बैठते हैं। इससे उन्हें अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इस पैकेज में प्रारंभिक शिक्षा को 10 स्तरों में बांटा गया

यह बात गौरतलब है कि मात्र अच्छे प्रशिक्षण से शिक्षकों के प्रदर्शन में सुधार आया लगता है। यह तथ्य आजकल प्रचलित इस नीति पर सवालिया निशान लगाता है कि स्कूली शिक्षकों से अच्छा काम करवाने का तरीका यही है कि उन्हें अल्पकालिक नियुक्ति दी जाए और असुरक्षा की तलवार उनके सिर पर लटकती रहे।

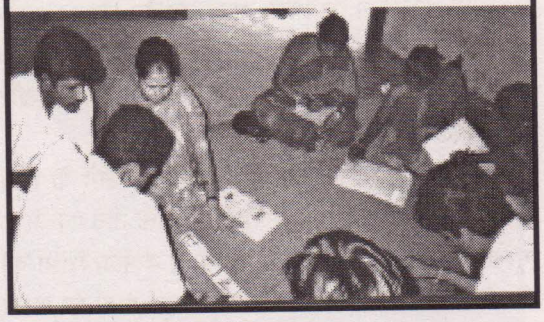

है और हो सकता है कि कोई बच्ची एक ही समय पर गणित के तीसरे स्तर पर और भाषा के आठवें स्तर पर हो। हो सकता है कि अधिक बच्चों वाली कक्षाओं में इसे लागू करना मुश्किल हो मगर कक्षा को बाल-स्नेही बनाने की दिशा में यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा गारंटी योजना तथा कुछ हद तक एकलव्य के पैकेज में बच्चों के एक-दूसरे से परस्पर सीखने को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दोनों में ही स्व-प्रेरित ढंग से गतिविधियों के माध्यम से सीखने को कक्षा संचालन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। एकलव्य के पैकेज में समस्या सुलझाने व विश्लेषण जैसे पहलुओं पर काफी ज़ोर है।

छात्रों का प्रदर्शन

अलग-अलग पैकेजों में बच्चों की उपलब्धि-स्तर के कई परीक्षण किए गए। अलबत्ता इनकी व्याख्या करना सबसे मुश्किल है। गुणात्मक अध्ययनों से कम-से-कम कुछ आम रुझान तो विश्वसनीय रूप से पता चलते हैं। दूसरी ओर एक आम पाठक को आंकड़े बहुत प्रभावित करते हैं किन्तु हो सकता है कि वे भ्रमित ही ज़्यादा करें। अध्ययन में एक प्रमुख समस्या यह रही कि टीम को एक गहन सर्वेक्षण के लिहाज़ से बहुत कम समय मिल पाया था। परिणाम यह रहा कि कुल दाखिल बच्चों में से मात्र 44

प्रतिशत का ही सर्वेक्षण हो पाया। और अजीब बात यह रही कि इस बाबत कोई जानकारी नहीं है कि कौन छूटा। अध्ययन की रिपोर्ट में यह उल्लेख उचित ही किया गया है कि यद्यपि सारे आंकड़ों को तालिकाबद्ध करके विश्लेषण किया गया है किन्तु इनमें से कोई अन्तिम निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है।

उपलब्धि-स्तर की जांच के लिए परीक्षण यह समझने के लिए बनाए जाते हैं कि पांच वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहता है। यह सम्भव है कि अलग-अलग पैकेज अलग-अलग रफ्तार व लय से चलते हों किन्तु यह सवाल तो उठता ही है कि अन्ततः इस पूरे प्रयास का नतीजा क्या रहा।

हुआ यह कि सर्वेक्षण में शामिल शिक्षा गारंटी योजना पैकेज की कक्षा 4 व 5 के स्तर पर बच्चों की संख्या इतनी कम थी कि उनके आधार पर कोई उल्लेखनीय निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। इस संदर्भ में एक और पेंच यह है कि शिक्षा गारंटी योजना के पैकेज में बच्चे अलग-अलग विषयों में अलग-अलग स्तर पर हो सकते हैं। उन्हें एक से दूसरे स्तर में स्थानांतरित करने का काम शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन के बाद ही किया जाता है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि इन बच्चों की तुलना उन पैकेजों के बच्चों से कैसे करेंगे जहां बच्चे बिना किसी परीक्षा के आगे बढ़ते रहते हैं।

फिर भी अध्ययन में, थोड़ा आश्चर्यजनक ढंग से, विभिन्न पैकेजों में बच्चों के प्रदर्शन की तुलना की गई है। वैसे इस तरह की तुलना स्वयं अध्ययन दल की इस स्वीकारोक्ति के विरुद्ध है कि उनके पास तुलना की कोई विधि ही नहीं है। इसके बावजूद यह तुलना की गई क्योंकि शायद सरकार का ऐसा आग्रह रहा होगा।

बहरहाल, इन आंकड़ों का जो भी महत्व हो, नज़र यह आता है कि शुरुआती वर्षों में अन्य दो पैकेजों के मुकाबले शिक्षा गारंटी योजना के छात्रों का प्रदर्शन बेहतर है। किन्तु बाद के वर्षों में एकलव्य पैकेज के छात्र अन्यों की अपेक्षा बेहतर हैं। वैसे यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यदि इन्हीं आंकड़ों का थोड़ा अलग ढंग से विश्लेषण किया जाए और कक्षाओं की परस्पर तुलना की थोड़ी अलग मान्यताएं ली जाएं तो शिक्षा गारंटी योजना के छात्रों के बेहतर प्रदर्शन की बात टिक नहीं पाएगी।

एक बेचैनी भरा निष्कर्ष यह है कि अभी काफी काम किया जाना शेष है। तीनों पैकेजों में की गई मेहनत के बावजूद स्थिति यह है कि 4-5 बरस की स्कूली शिक्षा के बाद भी घटिया प्रदर्शन दर्शाने वाले बच्चों की संख्या काफी ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि स्कूली शिक्षा के वैकल्पिक स्वरूपों के क्षेत्र में काफी काम व प्रयोग करने की ज़रूरत है।

मूल्यांकन और भावी दिशाएं

अपनी सारी सीमाओं के बावजूद भारतीय प्रबंधन संस्थान की यह रिपोर्ट एक उपयोगी समीक्षा प्रस्तुत करती है जो मध्यप्रदेश व अन्यत्र शिक्षा में सुधार के काम में मददगार हो सकती है। इससे प्रत्येक पैकेज की खूबियां व कमियां उभरकर आई हैं। राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठन और शिक्षा में रुचि रखने वाले अन्य लोग इस रिपोर्ट से काफी कुछ पा सकते हैं। दिक्कत यह है कि मध्यप्रदेश सरकार ने इन पैकेजों से उभरे सबकों को स्कूली मुख्यधारा में अंगीकार करने का कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया है। उदाहरण के लिए स्कूलों में गैर-कक्षा विभाजन व्यवस्था दिगन्तर द्वारा विकसित अत्यन्त महत्वपूर्ण नवाचार है, जिसे मध्यप्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना के तहत आज़माया गया।

शैक्षिक बदलाव एक पेचीदा मसला है और इस हेतु कोई बना-बनाया रास्ता उपलब्ध नहीं है। विभिन्न सम्भव समाधानों को आज़माने, अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखने का लम्बा रास्ता हमारे सामने है। मुख्य बात यह है कि हर स्तर पर प्रयोग चलते रहें और अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया चलती रहे।

शैक्षिक बदलाव एक पेचीदा मसला है और इस हेतु कोई बना-बनाया रास्ता उपलब्ध नहीं है। विभिन्न सम्भव समाधानों को आज़माने, अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखने का लम्बा रास्ता हमारे सामने है। मुख्य बात यह है कि हर स्तर पर प्रयोग चलते रहें और अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया चलती रहे।

लेकिन उस पर आगे कोई काम नहीं हो पा रहा है। मध्यप्रदेश की स्कूली व्यवस्था में कई बदलाव किए जा रहे हैं किन्तु गैर-कक्षा विभाजन को लेकर कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। यह समझना मुश्किल है कि राज्य सरकार अपने ही द्वारा कराए गए एक अध्ययन की इतनी उपेक्षा क्यों कर रही है।

इसी प्रकार से एकलव्य द्वारा किए शिक्षकों के नियमित गहन प्रशिक्षण के प्रयास भी अत्यन्त लाभदायी सिद्ध हुए हैं। लेकिन सरकार अपने सारे शिक्षकों को इस तरह प्रशिक्षित करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। इसके विपरीत शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक काम करवा-करवाकर उन्हें हतोत्साहित ही किया जा रहा है। अध्ययन में बताया गया है कि प्राशिका और सीखना-सिखाना पैकेजों के शिक्षक शिक्षा गारंटी योजना के शिक्षकों की तुलना में 3 गुना अधिक समय गैर-शैक्षणिक काम करते हैं। और स्कूल में पढ़ाई न होने के कारणों की सार्वजनिक छानबीन किए बगैर अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति को ही एकमात्र समाधान बताकर धकेला जा रहा है। सवाल यह है कि क्या गारंटी है कि पांच साल बाद भी ये शिक्षक पढ़ाने का काम करते रहेंगे। इसका जवाब नियुक्ति-बरखास्तगी में नहीं वरन् अच्छे प्रबंधन में है। और अच्छा प्रबंधन शिक्षकों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने का ही दूसरा नाम है।

सीखना-सिखाना पैकेज प्रदेश के प्रत्येक स्कूल में आज तक लागू किया जाने वाला सर्वोत्तम पैकेज रहा है। यह पहली बार है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने पाठ्यपुस्तक निर्माण की इतनी व्यापक प्रक्रिया चलाई और इसमें तमाम किस्म के स्रोत व्यक्तियों से इनपुट्स आमंत्रित किए। और अब उन्हीं पाठ्यपुस्तकों और उस पूरी प्रक्रिया को समाप्त किया जा रहा है। और यह सब करते हुए इन पाठ्यपुस्तकों की खूबियों-खामियों पर किसी सार्वजनिक बहस की भी गुंजाइश नहीं रखी जा रही है।

किसी भी तरह की प्रगति के लिए व्यवस्थित रूप से काम करना ज़रूरी है। शिक्षा में बदलाव के क्षेत्र में तदर्थवाद और सनक हावी रहे हैं और हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। अतीत के काम की समीक्षा और मूल्यांकन हमें अपनी मौजूदा रणनीतियों को पुख्ता बनाने और महत्वपूर्ण सबकों को अंगीकार करने का अवसर देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सुझाए गए हर कदम को मंजूर या नामंजूर करने के कारणों पर सार्वजनिक चर्चा हो।

शैक्षिक बदलाव एक पेचीदा मसला है और इस हेतु कोई बना-बनाया रास्ता उपलब्ध नहीं है। विभिन्न सम्भव समाधानों को आज़माने, अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखने का लम्बा रास्ता हमारे सामने है। मुख्य बात यह है कि हर स्तर पर प्रयोग चलते रहें और अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया चलती रहे।

कोई भी एक शैक्षिक पैकेज सारे जवाब नहीं दे सकता। उम्मीद तो इसी बात पर टिकी है कि विभिन्न स्थानों पर, अलग-अलग संदर्भों में, अलग-अलग संसाधनों के साथ कई प्रयास हो रहे हैं। जब विभिन्न प्रयासों को प्रोत्साहन और समर्थन मिलेगा तो यकीनन अच्छे विचार उभरते रहेंगे।

(स्रोत फ-ीचर्स)